(ख) और (ग) चूंकि खादी एवं ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के कुछ कर्मकार पूर्णकालिक आधार पर कार्य करते है और कुछ अंशकालिक आधार पर इसलिए खादी एवं ग्रामीण उद्योग संस्थानो द्वारा अपनाये जाने के लिए खादी एव ग्रामीण उद्योग आयोग ने उजरती दर के आधार पर मजदूरी की एक पद्धति निर्धारित की है, मजदूरी की राशि मजदूरी की निर्धारित उजरती दर के अनुसार कर्मकारो द्वारा किये गये कार्य पर निर्भर करती है। ग्रामीण उद्योगों के मामले मे सहयोगी क्षेत्र के अधिकतम संस्थानो द्वारा दिया जाने वाला पारिश्रमिक प्रत्येक उद्योग मे तथा कार्यकलाप के अनुसार अलग-अलग होता है। तथा प, ग्रामीण उद्योग मे किसी शिल्पी की दैनिक औसत आय लगभग 20/–रु० (बीस रुपये) प्रति दिन है।

(घ) जी, हा। खादी क्षेत्र मे उत्पादित सामान को कई देशो मे निर्यात किया जाता है। वर्ष 1989–90 के दौरान के० वी० आई० उत्पाद का निर्यात बढकर 5.54 करोड रुपये का हो गया जबकि यह वर्ष 1988–89 के दौरान, 5 05 करोड रुपये का था।

(ङ) खादी एव ग्रामीण उद्योग आयोग समय-समय पर के०वी०आई० क्षेत्र मे सस्थाओ द्वारा लगाये गये कर्मकारो की मजदूरी के स्त की पुनरीक्षा करता है। मूल्य सूचकांक के स्तर मे सामान्यत वृद्धि के साथ-साथ मजदूरी मे वृद्धि कर दी जाती है।

सन् 2025 तक सभी व्यक्तियों के लिए रोजगार

1533. श्री राम जेटमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोडा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2025 को उस वर्ष के रूप मे निर्धारित किया गया है जिस तक रोजगार के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ख) यदि हा, तो रोजगार के इच्छुक ऐसे युवा व्यक्तियों की अनुमानित संख्या क्या है और उस समय तक सृजित किए जाने वाले रोजगार अवसरों की अपेक्षित संख्या क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस संबध में कोई वार्षिक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हा, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो उसके क्या कारण है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय मे राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) और (ख) जी, नही। आठवी योजना दृष्टिकोण दस्तावेज मे परिकल्पित, 1990 के दशक की समाप्ति तक रोजगार के लिए 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर, सन् 2000 तक लगभग पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लक्ष्य पर आधारित है। चालू दशक के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन लोगो की संख्या जिनको रोजगार मुहैया कराना है तथा इसी तरह सृजित किए जाने के लिए अपेक्षित रोजगार अवसरो की संख्या लगभग 106 मिलियन होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी, नही। ब्यौरे तैयार किए जा रहे है और उन्हें आठवीं योजना दस्तावेज मे समाविष्ट कर लिया जाएगा।

महाराष्ट्र में गन्ने की पेराई की प्रतिष्ठापित क्षमता

1534. श्री राम जेटमलानी :

सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र मे गन्ने की पेराई की मौजूद प्रतिष्ठापित

क्षमता राज्य में गन्ने के उत्पादन की तुलना में पर्याप्त बढ़ी है जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और क्या केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कोई कारगर कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री कमल मोरारका) : (क) से (ग) 1989-90 के मौसम के दौरान मह राष्ट्र के चीनी कारखानों ने 365.8 (अनंतिम) लाख मी० टन गन्ने की पेराई की थी। महाराष्ट्र में इस मौसम में गन्ने के उत्पादन के बारे में ठोस अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार ने शीघ्र पेराई के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन में वृद्धि करने तथा शीघ्र पेराई के लिए मंजूर प्रोत्साहन की ही तरह मौसम के दौरान तथा मौसम के अंत में पेराई के लिए प्रोत्साहन देने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है।

पेराई के लिए प्रोत्साहनों की मंजूरी का मिल की वित्तीय जीव्यता से संबंध होता है, किंतु ये पेराई की क्षमता को सीधे प्रभावित नहीं करते है। तथापि, सरकार स्थिति की कड़ी निगरानी कर रही है।

Statement of Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi

1535 SHRI SURESH KALMADI Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Shahi Imam of Jama Masjid, Delhi had in a statement urged for the deployment of United Nations forces in India for the protection of minorities, and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) and (b) Such a statement has come to the notice of the Government The Delhi Administration is taking appropriate action in the matter.

दिल्ली पुलिस को राशन भत्ता

1536. **श्री लक्खीराम अग्रवाल** : क्या

प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के कार्मिकों को सस्ती दर पर राशन प्रदान कराने के बजाय 200/-रु० प्रतिमाह राशन भत्ता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, और

(ख) यदि हां, तो कब से और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास लम्बित नहीं है। तथापि, दिल्ली पुलिस ने अपने कार्मिकों को राशन भत्ता देने के लिए दिल्ली प्रशासन को एक प्रस्ताव भेजा है।

Naxalties in Andhra Pradesh

1537 SHRI KAILASH NARAYAN SARANG Will the PRIME MINISTER be pleased to state

(a) whether terrorist activities of the People's War Group (PWG) in Andhra Pradesh are on the increase and are spreading from there to the neighbouring Maharashtra as reported in the Hindu dated